भारतीय राजनीति की समसामयिक चुनौतियां

दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी

दिनांक 16-17 दिसम्बर 2022

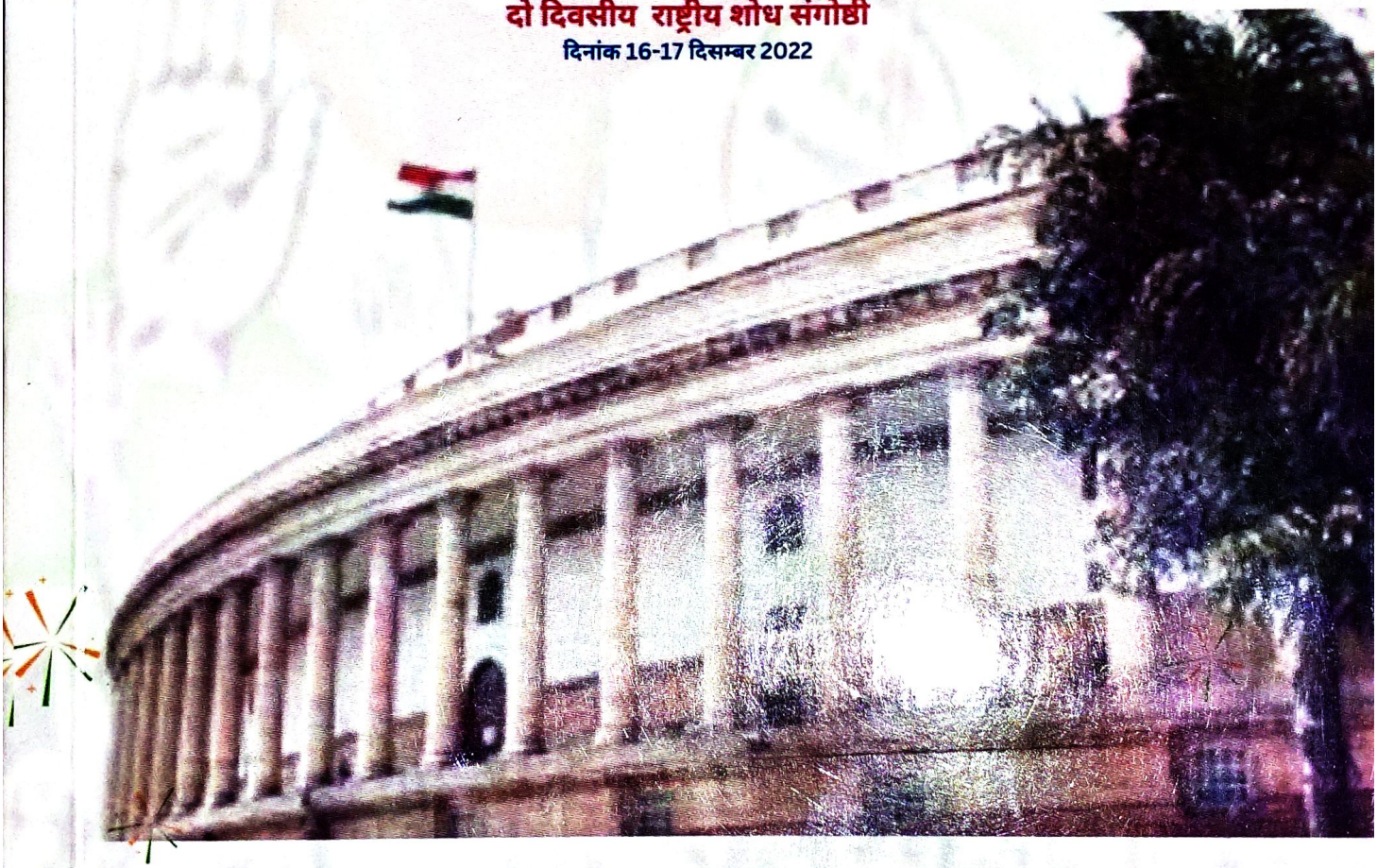

संरक्षक / प्राचार्य

डॉ. बी.डी. अहिरवार

सौजन्य: विश्व बैंक MPHEQIP के अंतर्गत IQAC के तत्वावधान में

श्री राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय बण्डा जिला सागर म.प्र.

Yajur Publishing House

Contemporary Challenges of Indian Politics

Chief Editor
Dr.Ashok Panya

Yajur Publishing House

Copyright © <Principal/Patron> 2023
All Rights Reserved.
ISBN:979-8-87-429824-1

December : 16-17-2022

Prise Rs.: 525.00

This book has been published with all reasonable efforts taken to make the material error-free after the consent of the author. No part of this book shall be used, reproduced in any manner whatsoever without written permission from the author, except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews.

The Author of this book is solely responsible and liable for its content including but not limited to the views, representations, descriptions, statements, information, opinions and references ["भारतीय राजनीति की समसामयिक चुनौतियां"]. The Content of this book shall not constitute or be construed or deemed to reflect the opinion or expression of the Publisher or Editor. Neither the Publisher nor Editor endorse or approve the Content of this book or guarantee the reliability, accuracy or completeness of the Content published herein and do not make any representations or warranties of any kind, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose. The Publisher and Editor shall not be liable whatsoever for any errors, omissions, whether such errors or omissions result from negligence, accident, or any other cause or claims for loss or damages of any kind, including without limitation, indirect or consequential loss or damage arising out of use, inability to use, or about the reliability, accuracy or sufficiency of the information contained in this book.

National Seminar
Dec.16-17-2022

Dr. B.D. Ahirwar
Principal/Patron

Seminar Coordinator
Dr.Kuldeep Yadav

Chief Editor
Dr.Ashok Panya

Editorial Board
Dr. Nitesh Oberine,
Dr.. Aakarsha Tiwari
Mr.shailendra Sakwar
Sanjay Thakur
Dr.Rashmi Priti Guru
Samir Panday

Govt.Shri Rajiv Gandhi College Banda (MP)
NAAC B Accredited

Organized By : World Bank under the Aegis of IQAC under MPHEQIP

Publisher:
Yajur Publishing House
6 Jeevan fakir c Ambabari
dahisar east , Borivali -400091(MS)
E-mail:yajurpress@rediffmail.com
Mo.no.+91-9630494707

Printer By
Repro Books Limited
Sun Paradise, 11th,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel,
Mumbai, Maharashtra 400013(MS)

27	ग्रामीण विकास में ई-प्रशासन की भूमिका	आदित्य कुमार त्रिपाठी	185-190
28	भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका एवं चुनौतियाँ	सोनम पाठक	191-197
29	समग्र ग्रामीण विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण के प्रयोग में सांसद आदर्श ग्राम योजना चुनौतियों व समाधान	कुलदीप चतुर्वेदी डॉ.अखलेश कुमार	198-208
30	भारत की राजनीति और वंशवाद	डॉ० नितीश ओबराइन	209-214
31	भारत में सुशासन की चुनौतियां	कमलेश कुमार चांवले	215-220
32	भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता की भूमिका	डॉ. अरुणिमा नामदेव	221-225
33	मीडियो की सामाजिक सरोकारों से दूरी एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता	आशाराम प्रजापति	226-230
34	भारतीय राजनीति में जातियों का महत्व: एक विश्लेषण	सुशील कुमार जॉगड़े, डॉ. दीपक कुमार गुप्ता	231-237
35	भारतीय सामाजिक राजनितिक परिवेश में सावित्रीबाई फुले एक प्रवर्तक	कीर्ति जाटव	238-244
36	भारतीय राजनीति में पंचायती राज की सफलता एवं चुनौतियाँ	डॉ.दीपक जॉनसन	245-249
37	भारत में जातियों का राजनीतिकरण	डॉ. रणवीर सिंह ठाकुर	250-252
38	स्थानीय स्वशासन एवं चुनौतियाँ	देवकी अहिरवार	253-258
39	भारत में आर्थिक चुनौतियां	डॉ. अक्षय कुमार जैन	259-261
40	स्थानीय स्वशासन एवं चुनौतियां	संजय कुमार अहिरवार	262-265
41	भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां	विनोद कुमार	266-272
42	भारतीय राजनीति में परिवारवाद : एक चुनौती	मनोज कुमार द्विवेदी	273-276
43	भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ	श्रीमती भुमानी बाई अहिरवार	277-285
44	भारतीय राजनीति मे क्षेत्रवाद तथा भाषावाद के संदर्भ मे विश्लेषणात्मक अध्ययन	ममता अहिरवार	286-294
45	पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण विकास	डॉ. प्रहलाद सिंह अहिरवार	295-301
46	भारतीय राजनीति में जातिवाद	अमीना खातून	302-308

समग्र ग्रामीण विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण के प्रयोग में सांसद आदर्श ग्राम योजना चुनौतियों व समाधान

कुलदीप चतुर्वेदी
असिस्टेंट प्रोफेसर(राजनीति विज्ञान)
शा. राजीव गाँधी पी.जी. कॉलेज अम्बिकापुर,(छ.ग.)
डॉ.अखलेश कुमार
प्राधयापक

Abstract(सार) :- भारत आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है, आजादी के उन्नायक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत के कल्याण का आधार समग्र व समावेशी ग्रामीण विकास को ही माना था। गांधीजी का मानना था कि "भारत भोगभूमि नहीं, अपितु मूलतः कर्मभूमि है।" गांधीजी के संपूर्ण दर्शन को अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण विकास उनके दर्शन का केंद्र बिंदु था, जिसमें ग्रामीण विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण प्रदान किया गया।

गांधीजी की ग्राम पुनर्निर्माण योजना स्वराज एवं स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित थी, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, पूर्णरोजगार, रोटी, मजदूरी, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, समानता एवं नई तालीम गांधीजी के ग्राम पुनर्निर्माण के प्रमुख स्तंभ थे।

भारत में गांधीवादी दृष्टिकोण को आधार बनाकर ग्रामीण विकास को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया है, इसी कड़ी में 11 अक्टूबर 2014 को "सांसद आदर्श ग्राम योजना" का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से गांधीवादी दृष्टिकोण का व्यवहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण पुनर्निर्माण की रूपरेखा बनाई गई।

प्रस्तुत शोध पत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियावयन गांधीवादी दृष्टिकोण की समीक्षा की गई है, तथ्य संकलन व विश्लेषण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गांव जयापुर वाराणसी का अध्ययन किया गया, साथ ही चुनौतियों का उल्लेख करते हुए समाधान के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्दः- सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण विकास, पूर्ण रोजगार, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज।

प्रस्तावना- भारत भूमि का केंद्र बिंदु वैदिक सभ्यता से लेकर अब तक ग्राम्य जीवन ही रहा है, भारत में पंचायती राज एक जीवन दर्शन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं अधिकतम लोगों का सर्वांगीण विकास करना है।ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक नीतियों में

ग्रामीण विकास को लगभग शून्य कर दिया। "आजादी के समय देश की लगभग 85% जनसंख्या गांव में निवास करती थी।" अधिसंख्य जनसंख्या के कल्याण के लिए महात्मा गांधी जी ने विकास का पैमाना ग्रामीण विकास को ही माना, "जब हिंसक साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर था, भौतिकता की होड़ में मानवता दब रही थी, ऐसे में गांधी जी ने नई राह दिखाई अहिंसा की,त्याग की व सर्वोदय की जिसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण प्रमुख था।"

गांधीजी की ग्राम पुनर्निर्माण योजना ग्राम स्वराज एवं स्वदेशी के सिद्धांतों पर आधारित थी। ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, पूर्णरोजगार, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण समानता एवं नई तालीम गांधीजी के ग्राम पुनर्निर्माण के प्रमुख स्तंभ थे।

गांधीजी के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विकास की रणनीति बनाई परंतु अभी भी अपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर न होने पर, ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए पृथक से सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया गया।

"भारतीय संस्कृति में गोद लेने का व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, इस योजना में सांसद की गांव के प्रति अगाध प्रेम होगा जिससे सांसद के मार्गदर्शन में गांवों को सामुदायिक भागीदारी के जरिए विकसित किया जाएगा।"

आदर्श ग्राम योजना (2014), वास्तव में गांधीवादी दृष्टिकोण व्यवहारिक अनुप्रयोग ही प्रतीत होता है, शोध पत्र में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस हद तक गांधी जी के सपनों को साकार कर सकी, इसमें क्या व्यवहारिक चुनौतियां है, व चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करके ग्रामीण विकास को तीव्र करने का प्रयास किया जाएगा।

शोध का उद्देश्यः-

वास्तविक ग्रामीण विकास की दशा व दिशा का मूल्यांकन करना।

ग्रामीण विकास में गांधीवादी दृष्टिकोण की भूमिका का अध्ययन।

ग्रामीण पुनर्निर्माण में सांसद आदर्श ग्राम योजना की भूमिका।

ग्रामीण विकास के समक्ष चुनौतियों व समाधान प्रस्तुत करना।

साहित्य पुनरावलोकन

सौरभ कुमार द्विवेदी ने "इंडियन जनरल आफ एप्लाइड रिसर्च वॉल्यूम 5 में "प्रोस्पेरिटी सांसद आदर्श ग्राम योजना एंड इंप्लीमेंटेशन इश्यू" में प्रमुख चुनौति प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही तकनीकी व प्रबंधकीय ज्ञान का अभाव।

डॉ. रुद्र ने रिसर्च गेट जर्नल में, "सांसद आदर्श ग्राम योजना इन इन्नोवेटिव मैनेजमेंट मॉडल फॉर इंपावरिंग रूरल इंडिया विथ इनोवेंटिव प्रोविटस" में योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास ना होकर सामुदायिक भावना का विकास, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, राष्ट्रगौरव, सांस्कृतिक पहचान को वरीयता देकर मानव का समावेशी विकास करना है।

आशुतोष पांडे (2016) ने, "इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च" नामक जर्नल में "गवर्नमेंट पॉलिसी सर्विस एज ए प्लेटफॉर्म फॉर को-ऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी" में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास के लिए संसाधन को जुटाने में को-ऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड अहम भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

सुनीता चौधरी ने "ग्रामीण विकास समीक्षा" अंक 56 ई-पंचायत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा पारदर्शिता में करके निर्णयन व नवपरिवर्तन में आसानी होगी।

इकबाल सिंह ने "भारत में ग्रामीण विकास" प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में असमानता को रेखांकित किया है, जिसके समाधान के लिए समंवित व समावेशी ग्रामीण विकास की आवश्यकता है।

रोमां रोला की पुस्तक,"महात्मा गांधी जीवन और दर्शन" लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज में गांधी जी के दर्शन का संपूर्ण अध्ययन समावेशित किया गया।

आर.के. प्रभु तथा यू.आर.राव की पुस्तक "महात्मा गांधी के विचार" नवजीवन पब्लिकेशन हाउस अहमदाबाद में गांधीजी विभिन्न मुद्दों तथा राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, पर्यावरणीय नैतिक पर विचारों का अध्ययन किया।

शोध पद्धतिः- प्रस्तुत शोध पत्र के निर्माण में साक्षात्कार, अनुसूची प्रश्नावली के साथ-साथ अवलोकन पद्धति का सहारा लिया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गांव जयपुर जिला वाराणसी का अध्ययन किया गया।

द्वितीयक स्रोत के रूप में शासन की गई रिपोर्ट, जनरल हुआ पुस्तकों का अध्ययन भी सम्मिलित हैं।

विश्लेषणः- गांधी दर्शन का मूल्य मन्तत्य अहिंसा पर आधारित सामाजिक संरचना एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें नागरिक समाज व राज्य दोनों के बीच परस्पर उत्तरदायित्वपूर्ण संबंधों का निर्धारण हों, उत्तरदायित्व पर आधारित यह व्यवस्था ही स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करती है।

ग्राम स्वराज की परिकल्पना गांधी ने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में की है। हर व्यक्ति की प्रायोगिक आवश्यकताओं की आर्पूर्ती से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। हर व्यक्ति चरखे से

स्वयं के लिए वस्त्र व कृषि के माध्यम से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें, ऐसा गांव "सादा जीवन उच्च विचार" के सिद्धांत को अपनाकर 'ग्राम स्वराज्य' या 'रामराज्य' को पा सकता है।
इसी धारणा को अपनाकर सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकेंद्रीकरण को वास्तव में लागू करने के लिए "ग्राम विकास योजना" का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए ग्रामसभा, महिलासभा, बालसभा, व्यवसायिक समूहों व स्थानीय संगठनों से विस्तृत चर्चा के उपरांत गांव के विकास की रणनीति बनाई जाती है, जिसमें सभी के मुद्दों व समस्याओं का समावेश होता है, जिसके उपरांत समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाता है। इस धारणा के माध्यम से विकास की रणनीति 'वाटम-टू-टॉप' उपागम के आधार पर तैयार करके गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है।
महात्मा गांधी सामाजिक समरसता के पक्षधर थे, उनका मानना था कि "गांव में किसी भी आधार पर असमानता भेदभाव छुआछूत नहीं होकर समानता होनी चाहिए।" उन्होंने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हित व विशेष कल्याण का समर्थन किया।
उनकी इसी धारणा को बल प्रदान करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सामाजिक रुप से अलग-अलग बड़े समूहों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के समावेशन एवं श्रमिक लिए सक्रिय प्रयास किए गए, आदर्श ग्राम जयापुर में सभी अनुसूचित जाति/जनजाति को बेहतर आवास, नल कनेक्शन, 24 घंटे अबाध विद्युत आपूर्ति निःशुल्क सुनिश्चित की गई।
गांधीजी के अनुसार "शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी को पूर्ण मानव बनाना है, पूर्ण मानवता का अर्थ है मानव में अधिभौतिक और अध्यात्मवाद का पूर्व समन्वय, सामंजस्य और संतुलन।
गांधी जी का शिक्षा दर्शन जो सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित है आज की बड़ी भारी आवश्यकता है।
गांधी जी कि इस धारणा को व्यवहारिक रूप स्वरूप प्रदान करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत "कक्षा दसवीं तथा शैक्षिक सुविधाओं को सभी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया, साथ ही मातृभाषा में अध्ययन को प्राथमिकता दी गई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों का स्मार्ट विद्यालयों में रूपांतरण, प्रौढ़ शिक्षा, ई-साक्षरता, ई-पुस्तकालय सहित ग्रामीण पुस्तकालयों का निर्माण किया गया।"
इसके साथ ही गांधीजी सर्वाधिक जोर व्यवसायिक शिक्षा देते पर देते थे, जिसके तहत् कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे एक ओर रोजगार के अवसर सुलभ हुए वहीं दूसरी

ओर श्रम के प्रति सम्मान भी बढ़ा इस तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना गांधी जी के सपनों को साकार करने में प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं।

गांधीजी के अनुसार "आत्मनिर्भरता, सहकारिता एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास ही ग्राम स्वराज व रामराज्य की परिकल्पना को साकार करेगा।" महात्मा गांधी ने ग्रामीण समुदाय को कृषि, पशुपालन, लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करके आत्मनिर्भर होने को प्रेरित किया गया है। गांधीजी ने कौशल विकास को प्राथमिकता प्रदान की उनका मानना था कि ग्रामवासी अपने कौशल में इतनी वृद्धि कर लें कि उनके द्वारा तैयार वस्तुओं की मांग देश के साथ विदेशों में भी हो।

गांधीजी सहकारिता अर्थात आपसी सहयोग को ग्रामीण विकास का महत्व आधार स्तंभ मानते थे, उनका मानना था कि एक-दूसरे के सामने होने से अच्छा एक-दूसरे के साथ खड़े होकर समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। गांधी जी सहकारिता के क्षेत्र को खेती, पशुपालन, वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र तक विस्तारित करने के पक्षधर थे।

गांधीजी के इन्हीं विचारों को आत्मसात् करते हुए उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्यम, डेयरी विकास और प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण, पारंपरिक उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया, सहकारिता को बढ़ावा देने वाले कारक गोबर बैंक मवेशी हॉस्टल, स्व-सहायता समूह, सामुदायिक भवन आदि की स्थापना की जा रही है।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आदर्श ग्राम जयापुर में बैंक, डाकघर, कौशल विकास केंद्र, सीडबैंक, हथकरघा उद्योग आदि की स्थापना की गई, समस्त कारक मिलकर गांव के विकास की नई-नई इबारत लिख रहे हैं।

वर्तमान दौर में विकास का पर्याय समावेशी व सतत् ही है, अर्थात् विकास का स्वरूप पर्यावरण हितैषी हो, गांधी के अनुसार "पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए सब कुछ है, परंतु किसी एक के स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं हैं।" गांधीजी का या विचार की सतत् विकास का दर्शन है।

गांधीजी भावना से अवगत होते हुए, भारत सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से कई परिवर्तन कारी सुधार किए जिसमें स्वच्छ और हरित ग्राम के लिए प्रत्येक परिवार में शौचालय व उसके उपयोग हेतु जागरूकता का अभियान चलाया गया, सड़कों किनारे वह खाली जगह वृक्षारोपण को बढ़ावा जल प्रबंधन के लिए वाटर शेड, वर्षा जल संचयन के

साथ-साथ लघु सिंचाई पद्धति (स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई) को बढ़ावा दिया गया। पशुधन विकास के माध्यम से जैविक खाद को बढ़ावा दिया गया जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे साथ ही पर्यावरण के अभिन्न घटक मृदा की रक्षा हो सके।

महात्मा गांधी न सिर्फ आर्थिक विकास के पक्षधर थे, बल्कि वे ग्रामीण जन समुदाय में नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के भी पक्षधर थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने श्रम के प्रति सम्मान, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, नशाबंदी जैसे मूल्यों के समावेश को भाव महत्वपूर्ण माना है।

गांधीजी के अनुसार, "ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की है कि वह अपनी रोटी के लिए श्रम करें, और जो व्यक्ति बिना श्रम के खाते हैं, वो चोर हैं।

गांधीजी के अनुसार "सत्य की खोज और क्रोध, स्वार्थ, घृणा आदि विकार स्वभावतः छूट जाते हैं, सत्य की खोज में प्राप्त होने पर मनुष्य प्रेम और घृणा, सुख और दुःख आदि के पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सत्य के माध्यम से परमार्थ की राह पर अग्रसर होता है।

गांधीजी के अनुसार "अहिंसा उसी प्रकार मानव का नियम है, जिस प्रकार पशुओं का हिंसा।" अहिंसा के द्वारा दैनिक जीवन परस्पर सच्चाई, विनम्रता, सहिष्णुता और दयालुता जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है।

इन्हीं विचारों से ओतप्रोत मानव में सर्वोदय की भावना का विकास होता है, जिससे वास्तव में समूचे मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, इस साध्य की प्राप्ति में न्यायसिकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

गांधीजी के इन्हीं विचारों को आत्मसात करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांव में शराब, धूम्रपान आदि की आदत को समाप्त व कम करने के लिए जागरूकता अभियान को विद्यालयों, युवा क्लबों, स्वास्थ्य, स्वयंसेवकों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

अहिंसा अपराधमुक्त गांवो को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समितियों के साथ-साथ युवाओं को संवेदनशील बनाया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय संस्कृति विरासत के संरक्षण के लिए भी ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत में आ रहे क्षरण को रोका जा सके, आदर्श गांव में आपसी सौहार्द बढ़ाने, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बरतने के साथ स्थानीय स्वशासन की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

चुनौतियाँः : -

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकास के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहते हैं कि "यदि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमें गांव से शुरुआत करनी होगी।" इसी दृष्टिकोण को आत्मसात करते हुए भारत सरकार ग्रामीण पुनर्निर्माण को विकास के केंद्र बिंदु में रखे हुए हैं, सकारात्मक प्रयासों के बावजूद भी परिणाम अधिक संतोषप्रद नहीं दिखाई देते हैं, ग्रामीण पुनर्निर्माण में प्रमुख चुनौतियों को निम्न बिंदुओं के अंर्तगत रखा जा सकता है।

ग्रामीण विकास का आधार ग्राम स्वराज है, जिसमें जनसहभागिता केंद्रिय धूरी का कार्य करती है, परंतु वास्तविक धरातल पर यह देखने को नहीं मिलता, माननीय सांसद श्रीमती माला रॉय के तारांकित प्रश्न क्रमांक 175 का जवाब 03/03/2020 को देते हुए स्वीकार किया कि अब तक 1812 गोद ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 1372 ग्राम पंचायतों ने ही विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम (VDPs) को तैयार करके भारत सरकार को भेजा, ग्राम विकास की रणनीति जन सहभागिता सुनिश्चित होती थी लेकिन जनसहभागिता के अभाव में ग्रामीण विकास अपनी गति को नहीं पकड़ पा रहा है।

ग्रामीण पुननिर्माण में अपेक्षित सकारात्मक बदलाव न आने के पीछे दलगत राजनीति की प्रमुख भूमिका रही है, केंद्र में सत्तारूढ़ दल को राज्यों में काबिल विपक्षी सरकारों द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है।

साक्ष्य के तौर पर लोकसभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 175 का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास ने 25 फरवरी 2020 को स्थिति SAGY के अंतर्गत गोद लिए गांव की सूची साझा की जिसमें पश्चिम बंगाल नें सिर्फ 10 गांव, तेलंगाना 53, ओडिशा 57, झारखंड 56 ग्राम पंचायतों को ही गोद लिया जा सका। एक अन्य उदाहरण छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के दौरान एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया।

वास्तव में ग्रामीण पुनर्निमाण बिना जनप्रतिनिधियों के विशेष रूचि के बिना संभव नहीं है, परंतु जनप्रतिनिधि इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, उदाहरण के तौर पर SAGY की चतुर्थ चरण में 2/3 सांसदों ने कोई ग्राम गोद नहीं लिया।

ग्रामीण पुनर्निर्माण में सबसे बड़ी चुनौति योजनाओं व कार्यक्रमों को वास्तविक धरातल पर सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित होना है, SAGY के अंतर्गत 2,33,405 प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली,परंतु एक 1,17,779 ही अब तक पूर्ण हो सके, जो वास्तविक क्रियान्वयन की दशा व दिशा को स्पष्ट करते हैं।

ग्रामीण पुर्निनर्माण के सूत्रधार ग्रामीण जन ही योजनाओं में यह देखने को मिलता है कि अधिकांश योजना आधारभूत ढाँचों के विकास तक सीमित होती है, ग्रामीण जनों के सामाजिक, संस्कृतिक पक्षों को प्राथमिक नहीं दी जाती है। इस बात की पुष्टि लोकसभा में भारत सरकार के ड्राफ्ट से होती है, जिसमें उल्लेख किया गया कि अगस्त 2021 की स्थिति में SAGY फेस-1 के अंतर्गत

सड़क	-	2990
अचल संपत्ति	-	937
पेयजल	-	917
शौचालय	-	1116
ऊर्जा	-	336

परियोजना को पूर्ण किया गया, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पक्षियों का उल्लेख नहीं है।

उपर्युक्त चुनौतियों के साथ-साथ चुनावों के दौरान या बाद में गुटबाजी या चुनावी हिंसा, जातिगत राजनीति, अशिक्षा जागरूकता का अभाव, ग्रामीण नौकरशाही का जवाब दे न होना, गरीबी व बेरोजगारी की चुनौतियां ग्रामीण पुर्निनर्माण के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न कर रही है।

सुझावः-

ग्रामीण पुनर्निर्माण के नवीन संकल्पना, आवश्यकताओं चुनौतियों के आलोक में निम्न सुझाव पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

जनप्रतिनिधियों खासकर सरपंच/उपसरपंच/पंचों को अपने-अपने गांवों में जनजागरूकता के सक्रीय प्रयास करने की आवश्यकता है, इसके अंतर्गत पंचायत भवन व गांव के प्रमुख मार्गों व दीवारों पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी चस्पा की जाए, माह में एक बार जागरूकता के लिए ग्रामीण नौकरशाही द्वारा कैंप लगाए जायें।

वास्तविक धरातल पर बिना जनप्रतिनिधियों की विशेष रूचि के बिना आमूल-चूल परिवर्तन संभव नहीं है, इसके लिए उन्हें परियोजना के क्रियान्वयन में असफल होने पर उनकी जबाबदेही तय की जाए, साथ ही इसकी रिपोर्ट बनाकर चुनाव के दौरान "रिपोर्ट कार्ड" को निर्वाचन आयोग के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए, ताकि चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए वह वास्तविक इच्छाशक्ति के साथ कार्य करेंगे।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्रामीण विकास के उत्थान में सभी दलों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, वित्त के आवंटन में कोई भेदभाव न हो, वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ही राज्यों को वित्त आवंटित किया जाए, साथ ही इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करके

जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, साथ ही आवंटित वित्त का प्रयोग न करने की स्थिति में जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

ग्रामीण विकास में सबसे प्रमुख भूमिका ग्रामीण की है, ग्रामीण नौकरशाही में कर्तव्य बोध को जागृत करने दंड व प्रोत्साहन का सिद्धांत अपनाया जाए, जो अधिकारी सीधे ग्रामीण विकास से जुड़े हैं, जैसे पटवारी, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक आदि की वेतन वृद्धि, पदोन्नति वार्षिक कामकाज की रिपोर्ट के आधार पर की जाए।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ अधोसंरचना का विकास न करने आम जनमानस में अपने समाज के प्रति कर्तव्य बोध नैतिक गुणों का समावेश, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक जागरण के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए सत्य, त्याग के लिए राजा हरिश्चंद्र, समाज के लिए त्याग के लिए राजा बलि, आदर्श चरित्र के लिए भगवान राम, कर्तव्य बोध के विकास के लिए श्री कृष्णा, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की वीर कथा का प्रचार प्रसार किया जाए, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से इन चरित्रों का चित्रांकन किया जाए गांव में वाचनालय आदि की स्थापना हो ताकि आम जनमानस में कर्तव्यबोध को जागृत किया जा सके।

जातिवादी राजनीति के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आरक्षण में मात्रात्मक रूप से बिना बदलाव किए बिना आरक्षित की जाने वाली सीटों की पद्धति में परिवर्तन किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक सीट को आरक्षित उस सीट के अल्पसंख्यक वर्ग को की जाए, ताकि समान जाति के लोगों को मत देने की धारण को ध्वस्त किया जाए, व समाज के सभी लोगों में सामंजस्य स्थापित हो।

चुनावों के बाद होने वाली हिंसा के समाधान के लिए व उपसरपंच की निर्वाचन पद्धति में बदलाव किया जाए, चुनावों में सर्वाधिक मत प्राप्त प्रत्याशी सरपंच व दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को उपसरपंच निर्वाचित किया जाए, ताकि गांव के अधिकांश मत का सम्मान होगा व दूसरे प्रत्याशी में पराजय का भाव न होकर साथ मिलकर काम करने का भी भाव विकसित हो।

निष्कर्षः-

गांधीजी के अनुसार "ग्रामीण विकास की संकल्पना स्वराज को सुराज में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केंद्रित हैं।" गांधी जी की इस भावना को आत्मसात करते हुए विभिन्न सरकारों ने अपने स्तर पर यथासंभव सराहनीय प्रयास किए हैं, वर्तमान सरकार ने दीनदयाल ग्रामीण कौशल मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के माध्यम से संभावित ग्रामीण में सकारात्मक योगदान दिया है, राजनीतिक दृढइच्छाशक्ति, जनसहभागिता, जवादेह नौकरशाही के संबंवित प्रयासों से ग्रामीण भारत का पूनर्निर्माण संभव है, जो एक स्वर्णिम भारत की राह प्रशस्त करेगा भारत व दुनिया को नई दिशा व दृष्टि देने में सक्षम होगा।

ग्रंथ सूची

1. इंडिया, 5/2/1925 पृष्ठ 45
2. पंत, राजीव मोहन (2020) "ग्रामीण विकास में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता" ग्रामीण विकास समीक्षा, अंक 6 जनवरी-दिसंबर 2020 हैदराबाद
3. सिंह सुधांशु, ;2015) "सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गांव" कुरुक्षेत्र जून 2015, नई दिल्ली
4. मीना जनक सिंह, ग्रामीण विकास के विविध आयाम(2010) ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, पेज नं. 07
5. एन.सी.ई.आर.टी. (2005) भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक पेज नं. 05
6. डॉ. पंत राजीव मोहन (2020), "ग्रामीण विकास में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता" ग्रामीण विकास समीक्षा, अंक 6 जनवरी-दिसंबर 2020 पेज नं. 01
7. डॉ. पंत राजीव मोहन (2020) ग्रामीण विकास में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता ग्रामीण विकास समीक्षा, अंक 6 जनवरी-दिसंबर 2020 पेज नंबर 02
8. सिंह सुधांशु "सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गांव," कुरुक्षेत्र (जून 2015) प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ,नई दिल्ली
9.डॉ. मिश्रा जय कुमार (2012) 21वीं सदी में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता , प्रत्यूष पब्लिकेशन गाजियाबाद पेज नंबर 202.
10. डॉ. पंत राजीव मोहन (2020), "ग्रामीण विकास में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता" ग्रामीण विकास समीक्षा, अंक 6 जनवरी-दिसंबर 2020 पेज नं. 03
11. झा. आरसी प्रसाद 2020 "ग्रामीण विकास में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता" ग्रामीण विकास समीक्षा, अंक 6 जनवरी-दिसंबर 2020 पेज नं. 55
12. डॉ. मिश्रा जय कुमार (2012) 21वीं सदी में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता , प्रत्यूष पब्लिकेशन गाजियाबाद पेज नंबर 33.
13. सांसद आदर्श ग्राम योजना, दिशा निर्देश ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार पेज नंबर 23
14.डॉ. पंत राजीव मोहन (2020), "ग्रामीण विकास में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता" ग्रामीण विकास समीक्षा, अंक 6 जनवरी-दिसंबर 2020 पेज नं. 01-02

15.डॉ. फार्मर मयूरी 2020 “ग्रामीण विकास में गांधी दर्शन की प्रासंगिकता“ ग्रामीण विकास समीक्षा, अंक 6 जनवरी-दिसंबर 2020 पेज नं. 40
16. यंग इंडिया 13-10-1921 पृष्ठ क्रमांक 325
17. यंग इंडिया 13-10-1921 पृष्ठ क्रमांक 254-255
18. प्रभु आर.के. व राव यू.आर गांधी जी के विचार (1994), नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पृष्ठ क्रमांक 117.
19. सिंह सुधांशु (2015) “सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गांव,“ कुरुक्षेत्र (जून 2015) प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ,नई दिल्ली
20. तारांकित प्रश्न 03-03-2020 को लोकसभा में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का जवाब।
21.http://saanyhi.gov.in
22. रिपोर्ट प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल छत्तीसगढ़।
23.http://factly.in
24. SAGY ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार Saanhi.gov.in